

[श्री सुरज प्रसाद]

और देश के अन्दर जो मजदूर हैं उनके पास परचाजंग कर्पसिटा नहीं है। विभिन्न तरह के टैंक्स लगाकर सरकार ने उनकी परचाजंग कर्पसिटा को खत्म कर दिया है। खासकर किसानों को उन्होंने उपज को लाभप्रद कामत नहीं दी। गत साल ईश को कामत धटा दा। जो काटन उत्पादक हैं उनको भी लाभप्रद कामत नहीं दी। विदेश से काटन मंगाकर उनके दामों में गिरावट पैदा कर दी। गत साल किसानों को कामत के रूप में एक अर्थ-शास्त्री ने अध्ययन किया कि उनको 50 रुपये कम मिलें। इसलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि जो देश के अन्दर विभिन्न उद्योगों में कपड़े में, खाद में, चीनी में, लोहे में बहुत सी चीजें जमा हो गयी हैं उनकी खपत हो इस दृष्टि से किसान जो देश का सबसे बड़ा उत्पादक है उसको लाभप्रद कामत देने की दिशा में क्या सरकार कदम उठाएगी ?

श्री उपसभापति: एक ही प्रश्न है बाकी सब छोड़िए।

श्री नारायण दत्त तिवारी: जो खाद के इस्तेमाल के बारे में सम्माननीय सदस्य ने आंकड़े दिए जो मेरे पास आंकड़े हैं वे उससे भिन्न हैं। सन 1980-81 में 55 लाख टन खाद का उपयोग हुआ था और 1981-82 में यह बढ़कर 61 लाख टन हो गया। तो खाद का प्रयोग कम हो रहा है या यह नहीं खरीदा जा रहा है ऐसी बात नहीं है खाद का इस्तेमाल बढ़ रहा है और उत्पादन भी हो रहा है। मेरे पास आंकड़े हैं कि अप्रैल-मई 1982 में नाईट्रोजन फर्टिलाइजर का उत्पादन 5.9 प्रतिशत, अप्रैल-मई 81 की तुलना में बढ़ा और फास्फोरिक फर्टिलाइजर 18.8 प्रतिशत बढ़ा। तो फास्फोरिक और नाईट्रोजन फर्टिलाइजर दोनों का अप्रैल-मई में उत्पादन बढ़ा है, फिर भी यह बात रिसेशन के संबंध में कही जा रही है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up Special Mentions.
Yes, Mrs. Ila Bhattacharya.

REFERENCE TO THE REPORTED INCREASE IN THE INCIDENTS OF DOWRY DEATH

SHRIMATI ILA BHATTACHARYA (Tripura): Sir, the increasing atrocities on women and murders of young brides for dowry have assumed serious proportions throughout the country. Young married women are burnt alive, maimed physically and mentally tortured by their husbands and in-laws. Day in and out, newspapers are revealing such gruesome atrocities committed on newly married women. In the very heart of Delhi itself and the number of dowry deaths has shown a big spurt in recent months. Not only innocent housewives, but also working women, were also victims of such atrocities. In Delhi itself, three cases involving two working women, a college lecturer and an employee of the Reserve Bank, have been reported and the laws have failed to check this inhuman atrocities on women. Apathy and indifference shown by the police officials and the local administration have emboldened the greedy in-laws to perpetuate such crimes. The existing laws have failed to check these inhuman crimes. Various women's organisations in the country have focused attention on this serious problem and have repeatedly drawn the Government's attention, but without any result. The Report of the Joint Committee of Parliament to examine the Dowry Prohibition Act is yet to come. The existing laws should be amended with a view to give stringent punishment to those indulging in such crimes.

[THE VICE-CHAIRMAN DR. (SHRIMATI NAJMA HEPTULLAH) IN THE CHAIR.

In order to protest against such crimes and draw the attention of the Government to the need for taking steps to stop such crimes, 'the Dahej Virodhi Chetna, Manch' has organised a protest march to Parliament today. I would urge upon the Government to look into this burning problem and take immediate steps to stop this menace and save the women from being burnt.

